

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा अप्रैल २०२३ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

I. चयन और नियुक्तियों का सारांश

(क) पीईएसबी, डीओपीटी ने माह अप्रैल, 23 के दौरान 06 (छह) पदों [सीएमडी के लिए 05 और निदेशकों के लिए 01] के लिए विज्ञापन जारी किए और 09 (नौ) चयन बैठकें [सीएमडी/एमडी/अध्यक्ष के लिए 04 और निदेशकों के लिए 05] आयोजित की गईं।

(ख) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची क और ख केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) में 19 मामलों (अर्थात् एमडी/सीईओ/कार्यात्मक निदेशकों) में नियुक्तियों का अनुमोदन किया। वर्तमान में, विभिन्न अनुसूची 'क' और 'ख' सीपीएसई में सीएमडी/एमडी/अध्यक्ष के कुल 50 पद और कार्यात्मक निदेशकों के 103 पद रिक्त हैं। विभिन्न न्यायाधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में 08 अध्यक्षों/सदस्यों की नियुक्तियों और स्वायत्त निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यपालकों की 02 नियुक्तियों को एसीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। मंत्रिमंडल सचिव/एसीसी ने समय पूर्व प्रत्यावर्तन (04), पुनः डिजाइन (01), गैर-सीएसएस पद पर नियुक्ति (01), विदेशी/कैप्टिव पद पर नियुक्ति (02) के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। इसके अलावा, 02 सीवीओ की नियुक्ति, 01 सीवीओ के कार्यकाल का विस्तार और 02 सीवीओ के समय पूर्व प्रत्यावर्तन को भी अनुमोदित किया गया था।

(ग) दिनांक 25.04.2023 की अधिसूचना जीएसआर 314 (अ) भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई, जिसके तहत आईपीएस (वेतन) नियमावली, 2016 में संशोधन किया गया है ताकि केन्द्र में 13 अधिकारियों (निदेशक, आईबी और निदेशक, सीबीआई के अलावा) में से 9 महानिदेशक स्तर के अधिकारियों को वरिष्ठता के आधार पर सर्वोच्च वेतनमान प्रदान किया जा सके।

(घ) अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा से आईएस के संयुक्त एजीएमयू संवर्ग में पदोन्नति द्वारा कुल 09 नियुक्तियां की गईं।

(ङ) हिमाचल प्रदेश (03), अरुणाचल प्रदेश (09) और मणिपुर (02) की राज्य सिविल सेवा/गैर-राज्य सिविल सेवाओं से आईएस में नियुक्त 14 अधिकारियों की वरिष्ठता/आबंटन के वर्ष के निर्धारण के आदेश जारी किए गए थे। इसके अलावा, एक आईएस अधिकारी के संबंध में अंतर संवर्ग स्थानांतरण और दो आईएस अधिकारियों के संबंध में अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति के विस्तार के आदेश भी जारी किए गए थे।

II. प्रशिक्षण और क्षमता विकास

(क) सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) ने माह अप्रैल, 2023 के दौरान 04 कैलेण्डर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 10 सीएसएस/सीएसएसएस संवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम और 05 दक्षता कार्यक्रम आयोजित किए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 606 उम्मीदवारों ने भाग लिया।

(ख) आईएस अधिकारियों के लिए चरण V का मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (10 से 28 अप्रैल, 2023 तक) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनए) में आयोजित किया गया। इसमें 1990-1996 बैच के 66 प्रतिभागी थे।

(ग) आईएसटीएम को 19 से 20 अप्रैल, 2023 तक राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी) द्वारा आकलित क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) मानकों के अंतर्गत उत्कृष्ट के रूप में "प्रत्यायन (एक्रेडिटेशन) प्रमाण-पत्र" प्रदान किया गया है।

(घ) क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) ने निम्नलिखित कार्यकलाप किए हैं :

i. क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) भारत के सहयोग से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) के लिए एक क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला का उद्देश्य आपदा न्यूनीकरण (वित्त पोषण सहित) के लिए मौजूदा प्रावधानों के आधार पर एसडीएमए का मूल्यांकन करना और साथ ही आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा आरंभ करना है। माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने समापन सत्र की अध्यक्षता की, जहां ब्रेकआउट समूहों ने आपदा प्रबंधन कर्मियों के समर्पित कैडर के माध्यम से उपशमन दिशानिर्देशों, आपदा उपशमन, जलवायु परिवर्तन के कारण उपशमन चुनौतियों और क्षमता वृद्धि पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

- ii. क्षमता विकास आयोग ने 21 और 22 अप्रैल, 2023 के दौरान चंद्रपुर वन अकादमी, महाराष्ट्र में अपने चिंतन शिविर का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पिछले दो वर्षों में सीबीसी की यात्रा को प्रतिबिंबित करने और भविष्य के लिए रणनीति बनाने का एक उत्कृष्ट अवसर था। चिंतन शिविर में सीबीसी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।
- iii. क्षमता विकास आयोग ने केस स्टडी विकसित करने पर केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (सीटीआई) और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंडिया रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित की गई थी।
- iv. क्षमता विकास आयोग द्वारा याशाडा, पुणे में अभिशासन उप-समिति रिपोर्ट पर एक एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का एजेंडा समिति के सदस्यों और विशेषज्ञों के बीच इस बात पर एक आम सहमति पर पहुंचना था कि केंद्र सरकार के आदर्श वाक्य "अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" को प्राप्त करने के तरीकों और उपकरणों को कैसे तैयार किया जाए। कार्यशाला में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिन्होंने वर्तमान शासन मॉडल और राष्ट्रीय सुशासन मॉडल की आवश्यकता पर अपने दृष्टिकोण साझा किए।
- v. सीबीसी की टीम ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान (एनएससीटीआई) पोर्टल के लिए राष्ट्रीय मानकों पर प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता के संबंध में सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद, आईएसटीएम, नई दिल्ली और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद का दौरा किया।
- vi. क्षमता विकास आयोग (सीबीसी) ने रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) के सहयोग से 25 अप्रैल, 2023 को 'रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (डीपीएसयू) और महाराणा के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर कार्यशाला' आयोजित की। कार्यशाला का आयोजन डीडीपी और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों को विभिन्न महाराणा और देश के अन्य प्रमुख पीएसयू से सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने के अवसर देने के लिए किया गया था।
- vii. क्षमता विकास आयोग ने ज्ञान साझेदारी के लिए योजनाओं और नीतियों में अनुसंधान केंद्र के साथ आशय पत्र (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए।

III. स्थापना मामले

- (क) दिनांक 25.04.2023 के का.ज्ञा.सं.ए-24011/23/2022-स्था.(छुट्टी) के माध्यम से अंग दाताओं को विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए।
- (ख) दिनांक 11.04.2023 के का. ज्ञा. सं. 12/4/2020-जेसीए के माध्यम से डॉ बी. आर. अम्बेडकर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारत भर में औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए दिनांक 14.04.2023 को अवकाश की घोषणा की गई।
- (ग) दिनांक 03.04.2023 [सा.क. नि 266(आ)] की अधिसूचना सं. 39018/01/2023-स्था.(ख) के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2023 जारी की गई।

IV. सतर्कता और अन्य संबंधित मामले

- (क) विभिन्न प्रयोजनों अर्थात् अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, परिवीक्षा आदि के लिए 36 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सतर्कता निकासी जारी की गई।

- (ख) संयुक्त सचिव के पैनलबद्धीकरण के लिए 115 आईएएस अधिकारियों की सतर्कता निकासी जारी की गई।
- (ग) लोक सभा सचिवालय से 01 विशेषाधिकार नोटिस प्राप्त और 01 का निपटान।
- (घ) वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईएएस अधिकारियों के पीएआर को स्वतः अग्रेषित करने के संबंध में समय-सीमा हेतु मुख्य सचिवों और भारत सरकार के सचिवों को अ. शा. पत्र जारी किए गए थे।

v. मिशन भर्ती के लिए 13 अप्रैल, 2023 को रोजगार मेला- सरकार में 10 लाख भर्तियां

दिनांक 13 अप्रैल, 2023 को देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मेले का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया था। सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री का स्वागत किया और माननीय प्रधान मंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम में उम्मीदवारों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम को दूरदर्शन द्वारा लाइव कवर किया गया था और सामान्य सोशल मीडिया चैनलों के अलावा 'इन शॉर्ट्स' के 'पब्लिक' ऐप के माध्यम से प्रचार भी किया गया था। रेल मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रिंट मीडिया प्रचार आदि के माध्यम से कार्यक्रम के आयोजन का समन्वय किया था। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास में सरकार के प्रयासों को प्रदर्शित करने वाली एक लघु फिल्म भी दिखाई गई।

vi. डीओपीटी के चिंतन शिविर की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति

17-18 फरवरी, 2023 को आयोजित डीओपीटी के चिंतन शिविर विचार-विमर्श के दौरान गठित फोकस समूहों की सिफारिशों के रूप में माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष की गई प्रस्तुति की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में कई सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है, जिन्हें संक्षेप में नीचे दिया गया है:

- (क) सभी नियमों और अनुदेशों के समेकन और अद्यतनीकरण के साथ-साथ अंतर्निहित प्रक्रिया के सरलीकरण और मानकीकरण को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है।
- (ख) प्रयोक्ताओं के छोटे (माइनर) प्रश्नों का उत्तर देने और इस प्रकार डीओपीटी के विभिन्न पत्र व्यवहार (कम्युनिकेशन) और नीतियों पर स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए एआई चैटबॉट अब डीओपीटी वेबसाइट पर क्रियाशील बनाए जा रहे हैं।
- (ग) डीओपीटी द्वारा प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता पर टिप्पणी करने के लिए एमडीओ को सक्षम बनाने हेतु एक फीडबैक तंत्र विकसित किया गया है। इसे ई-ऑफिस में लागू किया जाएगा।
- (घ) डीओपीटी के भीतर परामर्श की आवश्यकता वाले सभी मुद्दों को निपटाने के लिए एक अंतर-विभागीय समन्वय प्रणाली अब पूरी तरह से क्रियाशील है। ऐसे सभी मुद्दों की निगरानी ई-ऑफिस के माध्यम से की जा रही है और आमने-सामने की चर्चा के आधार पर बैठक में ही मुद्दों का निपटान करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित साप्ताहिक बैठकें बुलाई जाती हैं।
- (ङ) डीओपीटी में अधिकारियों को पेशेवर और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक मार्ग दर्शन (मेंटरिंग) प्रणाली शुरू की गई है। मेंटरिंग पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब तक मार्ग दर्शन प्राप्त करने वाले 172 अधिकारियों के लिए 52 मार्गदर्शकों की पहचान की गई है।
- (च) ईएचआरएमएस-2.0 के माध्यम से पदोन्नति की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, एपीएआर को ऑटो-फेच रूप से प्राप्त करने के लिए स्पैरो के साथ एकीकरण को पूरा कर लिया गया है।
- (छ) ईएचआरएमएस और आईजीओटी को जोड़ने सहित प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए ईएचआरएमएस का एक समर्पित मॉड्यूल स्थापित किया गया है।

- (ज) कर्मचारियों के दावों और लाभों आदि के समयबद्ध भुगतान के लिए विभिन्न प्रकार की डिजिटल सेवाएं, अब ईएचआरएमएस 2.0 में क्रियाशील हैं।
- (झ) जांच अधिकारियों/ प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों का पूल तैयार करने के लिए अधिकारियों का पूल तैयार करने संबंधी एक विज्ञापन जारी किया गया है।
- (ञ) आईएस और अन्य अधिकारियों के लिए अब एसओएलवीई (सॉल्व) और ई-एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय आधारित सतर्कता स्थिति (रियल टाइम विजिलेंस स्टेटस) उपलब्ध कराई गई है।

VII. ई-एचआरएमएस 2.0- कर्मचारियों को एंड टू एंड ऑनलाइन एचआर सेवाएं प्रदान करना

इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं (ई-एचआरएमएस) को एंड टू एंड ऑनलाइन एचआर सेवाएं प्रदान करने के लिए अपग्रेड किया गया है। ई-एचआरएमएस में अन्य बातों के साथ-साथ 24*7 पहुंच और उपलब्धता, एकल साइन-ऑन, ई-साइन, कर्मचारियों से विश्वास आधारित इनपुट तथा आई-गॉट, स्पैरो, प्रोबिटी पोर्टल और पीएफएमएस के साथ निर्बाध एकीकरण, एआई सक्षम उपकरण के साथ-साथ एक विश्लेषणात्मक और गत्यात्मक डैश बोर्ड की मुख्य विशेषताएं मौजूद हैं। ई-एचआरएमएस में शामिल होने के लिए सभी कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों से आग्रह किया जा रहा है। अब तक 48,876 कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस पोर्टल पर शामिल किया गया है।